उन पर काम करने वाले कर्मचारियो की टाईप की गति पर असर हुआ है जिसके कारण उनको दिक्कत होती है, और

(ग) यदि हा, तो सरकार ने इस बात को देखने के लिए क्या कदम उठाए है कि हिन्दी टाइपराइटर का की-बोर्ड भविष्य मे न बदला जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) से (ग) यह सही है कि देवनागरी टाइपराइटर के कुंजीपटल को कई बार परिवर्तित किया गया। यह भी सही है कि कुंजीपटल मे परिवर्तन करने से टाइपराइटर का प्रयोग करने वालो को कुछ कठिनाई होती है। लेकिन ये परिवर्तन कुंजीपटल मे सुधार करने के लिए तथा टाइपिंग की गति बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए थे। मई 1976 के बाद देवनागरी टाइपराइटर के कुंजीपटल मे कोई परिवर्तन नही किया गया है और न इसमे अब कोई परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है।

Representation on violent incidents in North-Eastern Region States

9313 SHRI SACHINDRALAL SINGHA Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether his Ministry received a number of representation from the M Ps of the North Eastern Region States about a number of violent incidents in these States during the last three months,

(b) if so, the details of the representations received,

(c) whether he will convene a meeting of the Chief Ministers and the Home Ministers of these States to discuss the Law and order situation of these States, and

(d) if so when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b) During the last three months only one such letter regarding incidents on Assam-Nagaland border was receieved

(c) & (d) During February—April, 1979, the Home Minister visited all the North-Eastern States/UTs and had an opportunity of discussing the law and order situation with the respective Chief Ministers Besides, the convened meetings with the Chief Ministers of Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh on 10, 11 & 12 April 1979 and again discussed, *inter alia* matters relating to law and order in those States

हिन्दी टाइपराइटरो का निर्माण

9314 **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या उद्योग मंत्री हिन्दी टाइपराइटर के निर्माण के बारे मे 29 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1528 के उत्तर के सबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस समय देश मे हिन्दी टाइपराइटर की कीमते बढ गई है और यदि हा तो क्या निर्माताओ ने टाइपराइटर की कीमतो को जब भी लिपि (किस्त) को बदला गया प्रत्येक बार बढाया और यदि हा तो कितना

(ख) क्या यह सच है कि इस समय हिन्दी टाइपराइटरो की मांगे बहुत अधिक है जो यह मांग इस समय हो रहे निर्माण से 8 गुनी अधिक है और खरीदारो को कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पडती है और यदि हा तो उस निर्माण बढाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये है, और

(ग) उन फर्मों या कम्पनियो के नाम क्या हैं जो इस समय टाइपराइटरो का निर्माण कर रही है और प्रत्येक कम्पनी के टाइपराइटर

का निर्माण लागत और बिक्री मूल्य कितना है और उस पर सरकारी कर कितना लगता है तथा उसका स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) हिन्दी टाइपराइटरों की मांग का कोई अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कारण इन टाइपराइटरों की मांग बढ़ रही है। टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिये उपलब्ध सुविधाएं मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है और यदि काफी क्रयादेश आर्डर किए जाते हैं तो विद्यमान एकक अपनी स्वीकृत क्षमता तक उत्पादन कर सकते हैं कि हिन्दी टाइपराइटरों के संबंध में बताया गया है कि वे दर-संविदा पर उपलब्ध हैं।

(ग) मैसर्स रेमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया, कलकत्ता, गोदरेज ऐण्ड बायर्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई, हेराल्ड कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास हिन्दी टाइपराइटरों का निर्माण करते रहे हैं। हाल ही में मैसर्स फासिट एशिया लिमिटेड मद्रास ने भी हिन्दी टाइपराइटरों का उत्पादन शुरु कर दिया है। टाइपराइटरों के मूल्य या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी पूर्ति एवम् निपटान के महानिदेशालय की दर-संविदा के अधीन 25 सें० मी० आकार के टाइपराइटरों का मूल्य 1620/- रुपए है तथा उस पर 20 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता है इस पर बिक्री कर तथा चुंगी जैसे अन्य शुल्क भी लगेंगे ।

जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी

9315. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ जिला उद्योग केन्द्रों में काम बिलकुल भी आरम्भ नहीं हुआ है और आवश्यक कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

पंजाब, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन तथा दिव, दादरा तथा नगर हवेली के राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में तथा देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अभी तक कुछ जिला उद्योग केन्द्रों ने कार्य करना शुरु नहीं किया

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम 1 मई, 1978 में शुरु किया गया था विभिन्न राज्यों में जिला उद्योग केन्द्र भिन्न भिन्न समय पर स्वीकृत किए गए थे। अनुभव से पता चलता है कि कार्यालय की स्थापना करने, कर्मचारियों की भर्ती करने तथा प्रशिक्षण आदि के प्रारंभिक कार्य को पूरा करने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। इस अवधि के बाद कार्यवाही योजना में हाथ में ली जाती हैं तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा वास्तविक कार्य शुरु करने से पहले कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

पंजाब तथा हरियाणा ने अपने प्रस्ताव कुछ देर से दिए । हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा दमन और दिव तथा दादर, नगर हवेली में भर्ती के नियम बनाने, चयन समितियों का गठन करने तथा भर्ती की प्रक्रियाओं पर निर्णय करने में कुछ विलम्ब हुआ था। किन्तु ये राज्य और संघ शासित प्रदेश अब अन्य राज्यों की बराबरी पर आ रहे हैं ।

जिला उद्योग केन्द्रों का प्रबन्ध करने वाले उपयुक्त स्थानीय व्यक्तियों की कमी के कारण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इस कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही अब इस विषय पर निर्णय करके